RAJYA SABHA

Friday, the 10th August, 2001/19 *Sravana,* 1923 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक उत्पादन लागत को कम किया जाना

* 281 श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन :†
श्री राम जेठमलानीः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे किः

(क) क्या नेफ्था पर आयात शुल्क में कमी करने की घोषणा से देश में उर्वरकों की उत्पादन लागत मं कमी आ जाएगीः

(ख) यदि हां, तो किस-किस उर्वरक की उत्पादन लागत मं कितनी-कितनी कमी होने का आकलन किया गया है।

(ग) क्या इस कमी का लाभ देश में उर्वरक का उपयोग करने वाले किसानों को मिलेगा, और

(घ) यदि हां, तो सरकार उर्वरकों की कीमतों में कमी करने की घोषणा कब तक करेंगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा)ः (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (घ) चूंकि उर्वरकों के निर्माण के लिए नेफ्था के आयात पर, पिछले वित्त वर्षों में नेफ्था पर लगाये गये आयात शुल्क की अपेक्षाकृत चालू वित्त वर्ष में नेफ्था के आयात पर लगाये गये सीमा शुल्क की दस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतःआयातित नेफ्था की खपत पर आधारित उर्वरकों की उत्पादन लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उर्वरकों का बिक्री मूल्य पहले ही उत्पादन लागत से काफी कम है। वर्तमान में उर्वरकों के बिक्री मूल्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रांजन सिंह ललन द्वारा पूछा गया।

Reduction in production cost of fertilizers

† *281. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN'-:††

SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether production cost of fertilizers in the country will go down with the announcement of reduction in import duty on Naphtha;

(b) if so, the names of fertilizers the production cost of which has been assessed to go down and by how much;

(c) whether benefit of this reduction will reach the fertilizer using farmers of the country; and

(d) if so, by when Government are likely to announce reduction in fertilizer prices?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) As there is no change in the rate of custom duty levied on import of Naphtha for manufacture of fertilizers in the current financial year *vis-a-vis* the import duty levied on Naphtha during the previous financial year, there will not be any change in the cost of production of fertilizers based on the consumption of imported Naphtha.

The selling prices of fertilizers are already far below the cost of production. There is no proposal at present to reduce the selling prices of fertilizers.

श्री राजीव सिंह ललन: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नेफ्था के आयात शुल्क में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कोई कमी नहीं की गयी है। महोदय, मेरा सीधा सवाल था कि इम्पोर्ट डयूटी में आप ने कितनी कमी की है। महोदय, इन

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The Question was actually asked on the floor of the house by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

के उत्तर से ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष इन्होंने इम्पोर्ट डयूटी में कमी की है। महोदय, नेफ्था की इम्पोर्ट डयूटी में कमी होने कारण उस के दो फॉल आउट्स हैं। पहला तो यह है कि देश के अंदर नेफ्था का उत्पादन इस से प्रभावित होगा, रिफायनरीज इस से प्रभावित होंगी और दूसरे जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उर्वरक का बिक्री मूल्य पहले ही उत्पादन लगात से काफी कम है, इसलिए उस में कोई कमी किए जाने का विचार नहीं है तो इस का सीधा लाभ तो ये किसानों को देने नहीं जा रहे हैं जबकि नेफ्था अगर कम हुआ है तो उससे उर्वरक का प्रोडक्शन कॉस्ट घट रहा है और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन यह कह रहे हैं कि उत्पादन लागत से बिक्री मूल्य पहले ही काफी कम है। यह कमी तो सब्सिडी के कारण है। उर्वरक पर जो सब्सिडी सरकार देती है उसके कारण बिक्री मूल्य कम है, लेकिन यह लाभ किसानों को मिलने नहीं जा रहा है। महोदय आप के माध्यम से मेरा सवाल यह है कि (ए) नेफ्था के आयात शुल्क मे कमी किए जाने के कारण अपने देश के जो नेफ्था उत्पादन हैं और जो रिफायनरीज हैं, उन पर इस का कितना असर पडेगा और (बी)नेफ्था की इम्पोर्ट डयूटी में कमी के कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी, उस का कितना लाभ सरकार किसानों को देने जा रही हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः चेयरमैन साहब, मेरा जवाब ऑनरेबल मेंबस ने पढ़ा होगा कि पिछले साल भी जीरो परसेंट डयूटी थी, उस के पहले भी जीरो परसेंट डयूटी थी, इसलिए फर्टीलाइजर पर डयूटी की कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन: सर, पार्टी 'बी' हुआ है।

श्री सभापति : ठीक है,पूछिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति जी , उर्वरक की जो वर्तमान मुल्य निर्धारण नीति है उस में काफी भ्रष्टाचार है । पिछले समय में उस में 500 करोड़ रुपए का घपला सब्सिडी में हुआ है जिस पर वित्त मंत्री ने उर्वरक मंत्रालय को लिखा है कि 500 करोड़ रुपए की ज्यादा सब्सिडी यूनिट्स को मिली है उस को वापिस किया जाए । इसी कारण वित्त मंत्री जी ने बजट भाषाण में युनिटवाइज रिटेंशन प्राइसिंग सिस्टम के बजाय ग्रुपवाइज रिटेंशन प्राइसिंग सिस्टम लागू करने की बात की थी लेकिन वह भी अभी तक अघर में लटका हुआ है और महोदय, फाइनेसियल एक्सप्रेस में खबर आई है कि सरकार इस पर अमल न करने का विचार रख रही है । चो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्रुप रिटेंशन प्राइसिंग सिस्टम को सरकार कब से लागू करना चाहती है ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः चेयरमैंन पर , इस सवाल का इस से कोई ताल्लुक नहीं है , लेकिन मैं जवाब इललिए देना चाहता हूं कि ई०आर०सी० की रिकमंडेशंस हैं कि उन को ग्रुपवाइज

बनाया जाए और उस की रिकमंडेशंस यह भी थी। जो इन का दूसरा सवाल था कि हर साल 7 परसेंट कीमत भी किसानों के लिए बढाई जाए और वह इसी साल से शुरू होनी थी, उस रिकमंडेशन पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी अपोजीशन आया , स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अपोजीशन आया , इंडस्ट्रीज का भी आया और लेबर युनियन्स का भी आया। उस सब को देखकर हम ने अभी उसे रिजेक्ट नहीं किया है। उस पर इंटर मिनिस्टीरियल डिस्कशन हो रहा है कि इसे किस हद तक लागू किया जाए क्योंकि इस बारे में चीफ मिनिस्टर्स से भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे इस सब को देखकर , उन रिकमंडेशंस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है , उस के लिए हम विचार कर रहे हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': 500 करोड़ का जो घपला हुआ , उसके बारे में नहीं बताया।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: उसका भी हो रहा है , उसका 450 करोड़ रुपया रिकवर किया है, बाकी इस साल रिकवर करने जा रहे है और भी जो होगा, कुछ सी०बी०आई० और कुछ हमारी जो रिकमेंडेशंस थीं , उस पर हम कर रहे हैं।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, the hon. Minister has tried to become very technical. It is true that the first part of the question relates to reduction of Import Duty. But reduction of Import Duty is not the only reasons for falling prices of naphtha. Every newspaper has reported and nobody can deny it. For example, Sir, I am holding a newspaper of July, the 14th,— "The national oil measures have slashed prices of naphtha, fuel oil and LFHS by Rs. 500 to Rs. 600 per tonne in the wake of slackening of industrial demand and lower international prices of these fuels." The substance of the question, the thrust of the question is since the prices have fallen, whether they have fallen due to reduction of Import Duty or otherwise, I would like to know whether the benefit of this fall in prices is going to the farmer who is the main consumer of the product naphtha which is the fertiliser. That is the question.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर , उसकी बात भई मैं बताया हूं कि इस बजट सेशन मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इम्पोर्ट पैरिटी प्रइस पर फर्टिलाइज़र यूनिट्स की सप्लाई हो। जो रिकमेंडेशन है ई०आर०सी० की , उसमें यही कहा गया है कि जो इम्पोर्ट पैरिटी हैं इस पर सप्लाई करें । उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और आई०ओ०सी० जो हमको 68 प्रतिशत नेफ्था सप्लाई करती है, उन्होंने मान लिया है कि 9 जुलाई से हम इम्पोर्ट पैरिटी पर आपको सप्लाई

करेंगे, लेकिन दूसरी कम्पनी से अभी हमारी बात चल रही है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इम्पोर्ट पैरीटी पर ही उनको सप्लाई किया जाए, लेकिन अब भी वे इम्पोर्ट पैरिटी से ज्यादा हमसे कीमत ले रहे हैं। हमने उसकी असैसमेंट की है कि हमें 275 करोड़ रुपए की युरिया पर बचत होगी इस इम्पोर्ट पैरिही की वजह से नैफ्था पर और 10 करोड़ रुपए की एफ०ओ० पर होगी इस तरह से यह 285 करोड़ रुपए बनती है। इससे 285 करोड़ रुपए का हमें फायदा होगा जब यह सप्लाई हमें इम्पोर्ट पैरिटी पर मिलने लगेगी।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. Sir, the Finance Minister in his Budget Speech had announced that the Government has decided to implement the recommendations of the Expenditure Reforms Commission, ERC, for a phased programme of complete de-control of Urea by 2006 and that Unit Specific Retention Price Scheme would be replaced by Group Concession Scheme as early as possible. ERC had proposed five groups to be constituted. The Fertiliser Ministry, I understand, carried out this exercise and the result was that an awfully distorted picture emerged. It was a case of complete topsy-turvy. Groups can be formed of units where similar conditions exist. In fertiliser industry conditions vary widely from unit to unit. To give an instance where coal is used to generate power the cost is low, the cost of generation power by gas is very high. And yet in the exercise that the Government did, coal units were clubbed with gas units to form a group. It is a mistaken belief that the group concept is a step towards complete de-control. There is no relationship whatsoever between group concept and de-control. My question is: What has been the result of the exercise carried out by the Government of India in respect of ERC proposals of constituting groups, and if the outcome is unsatisfactory, how does the Government propose to move in the matter and what are its next steps?

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: सर, मैं इसका पहले जवाब दे चुका हुं कि इस पर ईंटर मिनिस्टीरियल डिस्कशन हो रही है, इसका अभी फैसला करना है। मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता जब तक कि यह फैसला न हो जाए।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि

The selling

prices of fertilizers are already far below the cost of production, महोदय, बरौनी रिफाइनरी से लगा हुआ, बरौनी फर्टिलाइज़र ,हिंदुस्तान पर्टिलाइजर का प्लांट है। महोदय, यह नैफ्था-बेस्ड प्लांट है और यह बंद पडा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और इसी वजह से यह घाटे में है। महोदय, नैफ्था आजकल सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए युज नहीं होता। पर्टिलाइजर के नाम पर तो इसको हर प्रकार की सहुलियत दी जाती है। नैफ्था आजकल कार्बन बनाने के काम भी आता है जो मैकेनिकल स्ट्रैंथ है रबर इंडस्ट्री के लिए और इसलिए उसका घङल्ले से ब्लैक हो रहा है। इसके साथ-साथ नैफ्था को डिस्टिल्ड करके डीजल में मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से आज हमारे देश में इतना पौल्युटेड और ऐडल्टरेटेड डीजल बिक रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इतना पौल्युटेड और ऐडल्टरेटेड डीजल बिक रहा है आज उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में इतनी इंडस्ट्रीज खडी हो गई हैं जिन्हें नैफ्था कंसेशन पर मिल रहा है लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को नहीं मिल रहा है ताकि फर्टीलाइजर का उत्पादन हो और किसान को वह सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। यह कहा जाता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और उसका प्राइस बाजार में अच्छा मिल जाता है। मैं यह जानना चाहता हुं कि बरौनी फर्टीलाइजर जो एक नैफ्था बेस्ट इंडस्ट्री है, उसके बारे में आप क्या पैसला लेने जा रहे हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: ये जो 4 सिक कंपनियां हैं, उनके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कांस्टीटयुट हुआ है और जल्दी ही उसकी मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा कि किस-किस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है और किस-किस कंपनी को बंद किया जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमंडेशन के बाद ही कैबिनट इस बारे में फैसला करेगी।

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, I want to know from the hon. Minister as to what the present position is with regard to the HFCL units in regard to production of fertilizers. It is my first supplementary.

Part (b) of my supplementary, in this connection, is: The hon. Minister has already said that the Barauni fertilizer un't has been referred to the Group of Ministers. I would like to know as to when the Group of Ministers will submit its Report.

Part (c) of my supplementary is: I would like to know from the hon. Minister whether it is true that the Namrup unit of the HFCL is going to be bifurcated soon and whether any decision has been taken in this regard.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, इनके पहले सवाल के जवाब में मैं यह कहना

चाहता हुं कि जल्दी ही हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं, उसकी तारीख तो मैं अभी नहीं बता सकता। पहले हमने इसके लिए 19 तारीख तय की थी लेकिन कुछ मिनिस्टर्स की मजबुरी के कारण हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा है।

माननीय सदस्य ने नामरुप की जो बात कही है, उसका इस सवाल के साथ कोई लिंक नहीं है लेकिन मैं यह बताना चाहता हुं कि उसके लिए एक अलहदा कंपनी बनाने की रिकमंडेशन की गई है और वह कैबिनेट में जा रही है। इस तरह एक अलहदा कंपनी बनाकर हमने उसको चलाने का प्रस्ताव किया है।

Procurement of rail engines

*282. SHRI K. KALAVENKATA RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Indian Railways have not placed any orders or have slashed the orders for procurement of engines with the manufacturers;

(b) if so, the reason therefor;

(c) whether Central Trade Unions have approached the Prime Minister to intervene in the matter and get the orders isssued; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The production of locomotives is based on the actual requirements to meet the projected traffic arisings as also the availability of funds. Since the actual materialisation of freight traffic has been less than that anticipated for the IXth plan period, the requirement of locomotives has accordingly come down. The present production level is commensurate with traffic requirement and fund availability.

(c) Ministry of Railways has not received any such specific representation.

(d) Does not arise.